करें, क्या कभी आपने उनके साथ डिसकस किया ? यह घाटा लगता है, आखिर कब तक हम लोग नासिक प्रैस से इनको देते रहेंगे ? इसलिए क्या कोई मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग वहां की ट्रेड यूनियन के साथ करेंगे ताकि यह फिर रेपीटीशन नहीं हो घाटे का ?

श्री माधवराव सिंधिया : यूनियन के साथ चर्चा निरन्तर होती रहती है और डायलाग निरन्तर होता रहता है। हमारा यही प्रयास है कि होटल के हित को ध्यान में रखते हुए हम साथ ही साथ अपने स्टाफ और अपने जो मैनेजमेंट में जो स्टाफ है उसके भी हित को हम देखते रहे। वैसे तो रेश्यो है स्टाफ टू एक्सपेंडीचर . . .

श्री चतुरानन मिश्र : यह मैंने नहीं पूछा। मैंने पूछा कि उन ट्रेड यूनियनों के साथ कोई घाटे के विषय पर मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग होने से चर्चा होती रहती है. . . **(व्यवधान)** मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग कोई बात नहीं है।

श्री चतुरानन मिश्र : तो उनके साथ. . . **(व्यवधान)** कब तक हम लोग इस तरह का घाटा, आप ही बताइये हम नासिक प्रैस से कब तक देते रहेंगे ? वर्कर्ज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होने से वह भी उसके लिए साझीदार हो जाएगा।

श्री माधवराव सिंधिया : जो वर्तालाप करेंगे. .

श्री सभापति : इनका प्रश्न जो है वह वर्कर्ज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के बारे में क्या आप सोच रहे हैं ?

श्री माधवराव सिंधिया : जो चर्चा और वार्तालाप जो चलता है वर्कर्ज और स्टाफ के साथ उसमें एक प्रमुख बिंदु यह भी है कि घाटा कैसे पार करना और उसके ऊपर सैपेरेट मेमोरेंडम आफ् अंडरस्टैंडिंग घाटे के आर फुल बनाना पड़ेगा . । . . . **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : कोई इन-बिल्ट सिस्टम होगा कि सी० एम० डी० का स्थान रिक्त नहीं रहेगा, यह मैंने पूछा ?

श्री माधवराव सिंधिया : यह मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं यह प्रोपर प्लानिंग होनी चाहिए कि किसी का अगर रिटायरमेंट हो रहा हो तो 2-3 महीने पूर्व से ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए और यह जो स्थान है ज्यादा लंबे समय तक रिक्त नहीं होने चाहिएं।

It is a question of proper planning. I fully agree that . . .

श्री चतुरानन मिश्र : सहमत तो हैं, लेकिन हम तो एप्वायंटमेंट नहीं करेंगे, यह आप ही को करना है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं कह रहा हूं हमारी. . .

श्री चतुरानन मिश्र : हमने पूछा कि इन-बिल्ट सिस्टम कुछ होगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : होना चाहिए, लेकिन होगा या नहीं होगा ?

श्री माधवराव सिंधिया : सर, मैं इस बात को मान रहा हूं। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा।

Favouritism shown by DESU to temporary consumers

*103. DR. BAPU KALDATE : Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the report appearing in the Hindustan Times of the 14th April, 1992 regarding favouritism shown by DESU to temporary consumers by giving permanent connections without realising the heavy outstanding dues causing financial and legal problems ;

(b) if so, whether Government have made any inquiry into the matter ;

(c) if so, what is the factual position in this regard ; and

(d) what action is being taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d). No favouritism is shown by DESU to any consumer in the matter of recovery of outstanding dues in respect of a temporary connection before giving the permanent connection. The permanent connections to the Cinema at Azadpur and ten other consumers at Hudson Lines and Outram Lines quoted in the said News item were released on completion of the prescribed formalities, including payment of the last bill in respect of the temporary connections. Out of the amount of Rs. 2.89 lacs which subsequently became payable upto the date of dis-connection of the temporary connection of the Cinema, payment of Rs. 1.27 lacs has already been received and the consumer has been allowed to make the balance payment by the end of May, 1992.

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, इस उत्तर में अंतर्विरोध है, आप जरा उस उत्तर को पढ़ेंगे तो आपने खुद लिखा है कि अस्थायी कनैक्शनों के संबंधित बिल का भुगतान किए जाने सहित निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद जारी किए गए थे । इसका मतलब है कि उन्होंने भुगतान किया और आपने फिर कनैक्शन जारी किया । नीचे आप लिखते है कि उक्त सिनेमा हाल के अस्थायी कनैक्शन को काटे जाने की तारीख तक देय रकम 2.89 लाख थी । उसमें से 1 लाख 27 हजार दे दिए और कनेक्शन दे दिया । क्यों दिया ? जब तक वह पूरी बकाया राशि आपके पास नहीं देते हैं तब तक आपने उनको कनेक्शन क्यों दिया ? और मुझे यह जानकारी चाहिए कि यह कौन से सिनेमा वाले हैं ? मुझे यह भी जानकारी चाहिए कि जिस समय उनकी 2 लाख 89 हजार की बकाया राशि रह गयी थी तो आप ने उनको मई तक की इजाजत क्यों दी ? होटल कौन हैं ? किस तारीख की बकाया है और बगैर पूरे भुगतान के आप ने उनको इजाजत क्यों दी ?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय, आदरणीय कालदाते जी ने जो सवाल किया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि वह विजय सिनेमा है जो कि आजाद कालोनी में था, सन् 1976 से उसको टेंपरेरी कनेक्शन मिला हुआ था । फिर उसने परमानेंट कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिया और कई वर्षों तक उसको टेंपरेरी लायसेंस मिला था और टेंपरेरी ही कनेक्शन दिया गया था । फिर उसको पर्मानेंट कनेक्शन दिया गया । जब टेंपरेरी कनेक्शन के लोग उसकी जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि उसके ऊपर बकाया है और जैसे ही यह बात सरकार की जानकारी में आयी तुरंत ही उसको नोटिस दिया गया कि आप यह सब पैसा जमा करें । उन्होंने आधा पैसा जमा कर दिया और आधे की किस्त मांगी । वह किस्त के लिए भी हमने इजाजत दे दी । वह 20 मई तक पूरी किस्त दे देंगे और उनका पर्मानेंट कनेक्शन हो जाएगा ।

डा० बापू कालदाते : उन्होंने आधी किस्त नहीं दी है । आप खुद पढ़िए न । उन्होंने 1 लाख 27 हजार रूपए दे दिए और उनसे बकाया 1 लाख 62 हजार रुपए निकलता है जो कि आधे से ज्यादा है । अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल बिल्कुल साफ है कि जो 76 से चला रहा है, 76 से आपको बकाया नहीं देता है, आप उसको पर्मानेंट कनेक्शन देते हैं । आपने क्यों नहीं पूरा पैसा वसूल किया ? क्या कारण है कि उनको आपने इजाजत दे दी ? अब वह नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे 'फिर एक दफा बिजली काट देंगे

लेकिन पूरा बकाया वसूल किए बिना क्यों कनेक्शन दिया गया ? यह एक बात हुई। दूसरा जो उसमें सम्मिलित प्रश्न था, वह हडसन लाइंस के बार में था। उसकी बकाया के बारे में आपने कुछ कहा ही नहीं है। उसका क्या हुआ ? सर, मुझे क्या लगता है कि यह बड़े-बड़े जो बकायादार हैं, उनके लिए रियायतें मिलती हैं, लेकिन यहां एक मार्केट जल गया और इस बारे में मैंने आपको कितनी दफा चिट्ठी लिखी है कि भाई छोटे लोग हैं, उनको दीजिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। फिर बड़े लोगों के लिए छूट और रियायतें क्यों दे रहे हैं ? तो मैं जानना चाहूंगा कि हडसन वाले का क्या हुआ और उसको यह छूट आपने क्यों दी ? इसका जवाब मुझे चाहिए।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय दिल्ली में 38 हजार टेंपरेरी कनेक्शन है। दिल्ली की आबादी 93 लाख है और जब "डेसू" का निर्माण हुआ था, उस समय पूरे 50 मेगावाट बिजली का खर्च दिल्ली में था। आज वह 1500 मेगावाट का है और रोज हजारों लोग बिजली के कनेक्शन के लिए आते हैं तो इसमें छोटे और बड़े की बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति टेंपरेरी कनेक्शन लेता है तो आपको जानना चाहिए कि पर्मानेंट कनेक्शन का जितना चार्ज है उससे दोगुना चार्ज टेंपरेरी कनेक्शन का है। तो टेंपरेरी लायसेंस किसी व्यक्ति ने लिया और उसकी फीस देता रहा और जब उसने पर्मानेंट कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिया . . .

डा० बापू कालदाते : यही तो कारण है। वह चाहते हैं, अच्छा हो गया। टेंपरेरी में दोगुना लगता है, पर्मानेंट करा लो तो पैसा भी बच जाएगा और बकाया भी नहीं देना पड़ेगा।

श्री कल्पनाथ राय : कालदाते जी, आप इतने सम्मानित सदस्य हैं।

डा० बापू कालदाते : तभी तो पूछ रहा हूं।

श्री कल्पनाथ राय : आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैंने किसी को कनेक्शन देना है और मैं नहीं दे रहा हूं।

डा० बापू कालदाते : मैं आपके डिपार्टमेंट से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय आदरणीय कालदाते जी ने पूछा है 10 लोगों के संबंध में। आप जानते हैं कि टेंपरेरी कनेक्शन मेरेजेज में, सोशल फंक्शंस में या नए हाउस के कंस्ट्रक्शन के संबंध में दिए जाते हैं और टेंपरेरी कनेक्शन के चार्जेज पर्मानेंट से दोगुने होते हैं। कोई व्यक्ति टेंपरेरी कनेक्शन नहीं रखना चाहता, लेकिन पर्मानेंट कनेक्शन के लिए जब वह कामर्सियल फार्मलिटीज को पूरा कर देता है तो हम उसको पर्मानेंट कनेक्शन देते हैं। अब पर्मानेंट कनेक्शन की कैटेगरी अलग है और टेंपरेरी की अलग है। तो जब पर्मानेंट कनेक्शन दिया गया तो उस समय हमारे फायनेंस डिपार्टमेंट के लोगों ने यह जानना चाहा कि उनकी तरफ पैसा कितना बाकी है ? तो मालूम हुआ कि 2 लाख 89 हजार रूपया बाकी है। फिर उन्होंने तुरंत उनको नोटिस दिया और 1 लाख 27 हजार रूपए उन्होंने जमा किये। फिर किस्त के लिए उन्होंने कहा। उनको उसकी इजाजत दी गयी और वह 20 मई तक पूरा भुगतान कर देंगे। आज 5 मई है, 20 मई तक वह पूरा भुगतान कर देंगे।

सभापति महोदय : कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक वह बड़ा हो या छोटा हो, उसके संबंध में हम तो समानता का ही व्यवहार करते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसके साथ हम डंडेवाजी करेंगे। तो सभापति महोदय, आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि दिल्ली की जो बिजली की समस्या है, अभी सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुकूल दिल्ली का जो डेसू है उसका स्ट्रिक्चर करने के लिए, हमारे गृहमंत्री जी मौजूद हैं, हम दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड का दर्ज डेसू को देने जा रहे हैं ताकि

हम इस 93 लाख की जनसंख्या और इतने लोग जो बिजली के कंज्यूमर्स हैं, उनकी समस्या को हल कर सकें । ···(व्यवधान)···

डा० बापू कालदाते : सभापति जी, मंत्री जी को आप यह कहिए कि जो मैंने सवाल पूछा है, उसके बाहर का जवाब न दें । यह दिल्ली के इतने कनेक्शन हैं, यह तो हम जानते हैं । मेरा स्पेसिफिक सवाल है, मैं आपसे इतना ही पूछता हूं कि 20 मई तक अगर पैसा नहीं देगा तो आप क्या करने वाले हैं ? मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 मई की स्थिति हमको बता दें कि उसने दे दिए हैं पैसे ।

श्री कल्पनाथ राय : सभापति महोदय जैसा कि माननीय कालदाते जी ने कहा है, इस इरेगुलेरिटि का पता लगा तो हम उनसे पैसा ले रहे हैं । यह इरेगुलरिटि हुई, इसके लिए हमने विजलेन्स डिपार्टमेंट को जांच के लिए नियुक्त कर दिया है । यह विजलेन्स डिपार्टमेंट , जो हमारे डेसू का एक विंग है, वह जांच भी कर रहा है । आप विश्वास रखिए कि हम पैसा लेने के लिए सब तरीके अपनाएंगे और पैसा मिल जाएगा ।

डा० बापू कालदाते : 20 मई तक ?

श्री सभापति : आप पूछ रहे है कि अगर 20 तारीख को नहीं दिया तो क्या करेंगे ? ···(**व्यवधान**)··· अभी आपने कहा कि 20 तारीख तक मिल जाएगा । वह पूछ रहे हैं कि अगर 20 को नहीं मिला तो आप क्या करेंगे ?

श्री कल्पनाथ राय : बापू कालदाते जी को एक पत्र लिखकर सूचित कर देंगे कि अभी कृपया नहीं मिला है और 15 दिन का और नोटिस देंगे ।

डा० बापू कालदाते : यह पैसा मिला है, इतना सूचित करिए ।

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Bhandare.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : Sir, arising out of this question on connection and disconnection, I think the basic policy of the DESU is totally fallacious. It does not give electric supply to the so-called unauthorised persons. We had the -same problem in Bombay and, as early as in 1960 .... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN : You see, the question is restricted to the news item in "The Hindustan Times".

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : All right, Sir. Like air, electricity and water cannot be denied to any human being. But the whole difficulty is that because they refuse to give electricity, there is a large-scale theft of electricity, there is large-scale corruption.

MR. CHAIRMAN : What is your question ?

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : The question is whether they will change this policy of disconnecting and opt for the policy of giving connection and recovering lawfully the dues from all the residents of Delhi.

SHRI KALP NATH RAI : Sir, Delhi is expanding and is having a population of obout 93 lakhs. Only because of this, the Sarkaria Commission has recommended that the DESU cannot solve the problem of power supply in Delhi and that has to be converted into the Delhi State Electricity Board so that services to the consumers, to the people of Delhi, can be maintained.

MR. CHAIRMAN : What about his suggestion that there should be no disconnection ? .... (*Interruptions*) ... Mr. Bhandare has suggested that there should be no disconnection.

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : "Connection and recovery." This should be the policy .... (*Interruptions*) .... I do not want the defaulters to be protected. I want the very innocent citizens of Delhi to be given electric supply. That is the purpose of my question, Sir. .... (*Interruptions*) ...

SHRI JAGESH DESAI : What about overcharging ? .... (*Interruptions*) ...

SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE : We are all talking of innocent residents .... *(Interruptions* ....

श्री सभापति : देसाई जी, आप दोनों मिलकर बंबई में बात कर लें। यहां हाऊस को छोड़ दें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अभी जवाब देते हुए कहा कि आजादपुर का जो यह सिनेमा है, उसके 1976 में टेंपरेरी कनेक्शन मांगा था और दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि छह साल तक यह कर्जा क्यों बढ़ता रहा ? इसकी क्या जानकारी है ? और, जो डिपार्टमेंट के आफिसर, जिन्होंने यह सब होने दिया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है या नहीं की है ? मैं इस प्रकार के सिनेमा वालों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह गड़बड़ है और इसमें कहीं न कहीं मिली-भगत है।

Why no action has been taken against the concerned officers ? Why.?

तो यह 1976 में टेम्परेरी कनेक्शन दिया गया और छह साल तक यह चलता रहा। आखिर क्यों ?

श्री कल्पनाथ राय : सभापति जी, यह जो सिनेमा था, उसको टेम्परेरी लाइसेंस हर साल दिया जाता था और जब तक उसको टेम्परेरी लाइसेंस रहा, टेम्परेरी कनेक्शन लेता रहा, जब सिनेमा परमानेंट हो गया तब उसने परमानेंट के लिए एप्लाई किया और टेम्परेरी कनेक्शन का चार्जिज दुगुना होता है और परमानेंट का उससे आधा होता है, अगर कोई टेम्परेरी कनेक्शन लेगा तो उससे डेसू को तो लाभ है लेकिन जब उसे परमानेंट लाइसेंस मिल गया तो उसने परमानेंट कनेक्शन के लिए कहा, इसलिए उसे परमानेंट कनेक्शन दिया गया।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय सांसदों के बड़े पक्षधर हैं और मंत्रियों को बिजली का बिल नहीं जमा कराना पड़ता है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास कोई ऐसी योजनाना है जिससे सांसदों को बिजली का कोई बिल न आए और जैसे अन्य सुविधाएं दी गई है, उसी तरह बिजली की भी सुविधा दी जाए ? अगर है तो ..(**व्यवधान**)..और मंत्रियों को जैसे बिजली का कोई बिल नहीं आता है, क्या मंत्री महोदय सारे सांसदों की शुभकामना और आर्शीवाद लेकर के और अधिक उन्नतिशील पद पर बैठेंगे इसके लिए क्या विचार करेंगे ? अगर नहीं है तो क्या विचार करके योजना बनाएंगे, कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम करेंगे ताकि बिजली मंत्री के रूप में इनका काम अजर-अमर रहे ?

श्री सभापति : सब एम० पीज० कहीं आर्शीवाद पाने के लिए कुछ करेंगे ? आशीर्वाद लेना हो तो करो।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इनको आशीर्वाद के साथ-साथ शुभकामना भी मैंने दी है, इस पर कुछ ऐसा करें कि.....

श्री सभापति : आपने बड़ी अच्छी बात कही है, आर्शीवाद से इनकी पदोन्नति हो जाएगी, इसलिए इनका आर्शीवाद लें, अब यह इन पर है कि आर्शीवाद लेते हैं या नहीं लेते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसा...

श्री सभापति : वह आशीवाद लना चाहता है लेकिन सरकार साहब की तरफ देख रहे हैं, आर्शीवाद लेने देंगे क्या।..(**व्यवधान**)..

श्री जगेश देसाई : बंद करवाओ, बंद करवाओ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जैसा आदरणीय पाण्डेय जी ने कहा है, सदन के नेता यहां मौजूद हैं, मैं पार्लिमेंटरी मिनिस्टर को भी इनकी भावनाओं से अवगत कराऊंगा और प्रधान मंत्री जी से भी यह कहूंगा कि विधायकों की भांति संसद सदस्यों को भी बिजली का बिल न देना पड़े।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इसको करा दीजिए क्या आप आश्वासन दे रहे हैं ?